



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 26, 2018/वैशाख 6, 1940

No. 269]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 26, 2018/VAISAKHA 6, 1940

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

(बीमा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 401(अ).—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 24 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीमा लोकपाल नियम, 2017, का संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, **जिसे केन्द्रीय सरकार बनाने का प्रस्ताव करती है**, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको ऐसे भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, 45 दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त होते हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, तृतीय तल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों को बीमा लोकपाल (संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. बीमा लोकपाल नियम, 2017 में,

(i) नियम 5 के उप-नियम (2) में खण्ड (vi) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा:—

“(vi) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम का अध्यक्ष या भारतीय साधारण बीमाकर्ता (सार्वजनिक क्षेत्र); संघ (जिप्सा) का अध्यक्ष, परंतु वे बीमाकर्ताओं की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य न कर रहे हों”;

(ii) नियम 10 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा:—

“(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नियत वेतन के लागू होने की प्रभावी तारीख वह होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए:

परंतु यह कि लोकपाल को देय अन्य भत्ते तथा परिलब्धियां, जिसके अंतर्गत उनके लागू होने की प्रभावी तारीख भी है, वह होगी, जो बीमाकर्ताओं की कार्यकारी परिषद के द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अवधारित की जाए।”

[फा. सं. 14019/22/2010-बीमा-II]

एन. श्रीनिवास राव, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 413 (अ), तारीख 27 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

(INSURANCE DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2018

G.S.R. 401(E).—The following draft of certain rules to amend the Insurance Ombudsman Rules, 2017 which the Central Government proposes to make, in exercise of powers conferred by section 24 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published are made available to the public;

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period specified above will be considered by the Central Government;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Finance, Department of Financial Services, Third Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Insurance Ombudsman (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Insurance Ombudsman Rules, 2017, —

(i) in rule 5, in sub-rule (2), for clause (vi), the following clause shall be substituted, namely:--

“(vi) the Chairman, Life Insurance Corporation of India (LIC of India) established under the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956) or the Chairman, General Insurers’ (Public Sector) Association of India (GIPSA) provided they are not acting as Chairperson of the Executive Council of Insurers.”;

(ii) in rule 10, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(2) The effective date for application of the fixed pay referred to in sub-rule (1) shall be such as may be determined by the Central Government:

Provided that the other allowances and perquisites payable to the Ombudsman including the effective date for their application shall be such as may be determined by the Executive Council of Insurers with the prior approval of the Central Government.”

[F.No.14019/22/2010-Ins.II]

N. SRINIVASA RAO, Economic Advisor

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification under G.S.R. 413 (E), dated the 27th April, 2017.